

मध्यप्रदेश में स्वच्छता

विकास संवाद

ई.7/226, प्रथम तल, धनवन्तरी काम्पलेक्स के सामने, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल, म.प्र.

फोन - 0755- 4252789, vikassamvad@gmail.com

बिन्दुवार

- ◆ मध्यप्रदेश में समग्र स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 3311313 शौचालयों (गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए) का निर्माण किया जाना था पर बने केवल 669320 यानी 20.21 प्रतिशत।
- ◆ लक्ष्य यह था कि 56583 स्कूलों में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी पर अब तक 20974 स्कूलों में यह व्यवस्था नहीं हो पाई।
- ◆ राज्य के 50263 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केवल 11627 केन्द्रों में छोटे बच्चों के लिये शौचालय की व्यवस्था है। अभियान में 6923 केन्द्रों में शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया गया था किन्तु बने सिर्फ 2309 केन्द्रों में।
- ◆ समग्र स्वच्छता अभियान के लिये मध्यप्रदेश को 422.55 करोड़ रुपये आवंटित हुये हैं जिसमें से 137.16 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये हैं।
- ◆ मध्यप्रदेश के कुल स्कूलों में से केवल 19.51 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिये शौचालय हैं।
- ◆ मध्यप्रदेश के कुल स्कूलों में से केवल 30.47 स्कूलों में साझा शौचालय हैं।
- ◆ देश में होने वाले तमाम मलेरिया प्रकरणों में से 24 प्रतिशत प्रकरण मध्यप्रदेश में दर्ज होते हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के 40 प्रतिशत प्रकरण मध्यप्रदेश में ही दर्ज होते हैं।

भूमिका

मध्यप्रदेश में स्वच्छता को स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुये मुद्दे के रूप में देखने के बजाये आमतौर पर एक निर्माण कार्यक्रम के रूप में ज्यादा महत्व दिया गया है। यही कारण है कि सितम्बर 2000 से शुरू हुआ समय स्वच्छता अभियान कभी भी आम आदमी से जुड़ा हुआ प्रयास बन कर सामने नहीं आ सका। अव्यावहारिकता के धरातल पर खड़े इस अभियान में अपेक्षा यह की गई थी कि वे 88 प्रतिशत लोग जो जलवहित शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं। वे उनका निर्माण करें या करवायें और खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति का त्याग करें। इस सोच को लागू करने के लिये सरकार ने शौचालय बनवाने के लिये 625 रुपये की लागत का आंकलन किया और तय किया कि 500 रुपये की राशि का अंशदान केन्द्र और राज्य सरकारें करेंगी।

इसके साथ ही सरकार ने हर जिले में शौचालय निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली सामग्री की उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिये एक केन्द्र के लिये साढ़े तीन लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया था।

मध्यप्रदेश में 3311312 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय बनवाने, 801 महिला स्वच्छता परिसर, आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय बनाने के लिये कुल 422.55 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है। इस राशि में केन्द्र और राज्य सरकार के अलावा आम लोगों (यानी हितग्राहियों से) 55.75 करोड़ रुपये का अंशदान अपेक्षित है।

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र बदलाव के लिये रणनीति नामक दस्तावेज के 94 पृष्ठों में स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल के मुद्दे पर कुल जमा 71 शब्दों में बात की गई है। इससे पता चलता है कि आज भी संक्रमण और मलेरिया-डायरिया जैसी परजीवी बीमारियों से निपटने के लिये पीने के साफ पानी और स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने की इच्छा शक्ति पैदा नहीं हुई है।

मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य नीति में एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिससे यह पता चले कि सरकार स्वच्छता और स्वास्थ्य के परस्पर सम्बन्धों को महसूस और स्वीकार करती है। अब भी व्यवस्था का पूरा ध्यान बीमारी के इलाज पर केन्द्रित है वह बीमारी के कारणों के प्रति अब भी सजग नजर नहीं आती है।

“देश में होने वाले तमाम मलेरिया प्रकरणों में से 24 प्रतिशत प्रकरणों का योगदान मध्यप्रदेश की तरफ से होता है। प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (एक तरह का सबसे गंभीर मलेरिया) के 40 फीसदी प्रकरण मध्यप्रदेश में दर्ज होते हैं। मलेरिया के कारण होने वाली कुल मौतों में से केवल मध्यप्रदेश में ही 20

प्रतिशत होती हैं। मध्यप्रदेश की 60 फीसदी जनसंख्या मलेरिया प्रभावित और ज्यादा संभावित क्षेत्रों में रहती है। पिछले 2 वर्षों में मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों में मलेरिया और गैर-आदिवासी इलाकों में प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के प्रकरणों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इसी दौरान सकंमित परजीवी से पैदा होने वाले चिकनगुनिया बुखार ने चार जिलों के लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। वर्तमान में 11 जिले इस बीमारी की चपेट में हैं¹

¹ मध्यप्रदेश ड्राफ्ट हेल्थ सेक्टर रिफार्म स्ट्रेटेजी, पृष्ठ 9,10

गांवों की स्वच्छता का सवाल

शिवपुरी के गुगवारा गांव में जीवन में सफाई-स्वच्छतापूर्ण व्यवहार शामिल करने के उद्देश्य से जागरूकता के प्रयास किये गये। एक मर्तबा ऐसे ही एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांव के आदिवासियों के सामने एक बाल को मानव मल से स्पर्श करा कर पीने के पानी के एक गिलास में डुबो दिया। कोई भी व्यक्ति उस पानी को पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। होता भी कैसे? फिर यह चर्चा हुई कि जब यह पानी नहीं पिया जा सकता है तो फिर जब मक्खी मानव मल पर मक्खी बैठ कर हमारी खाने की वस्तुओं और पानी की दूषित कर देती है तो वह पानी कैसे पिया जा सकता है? इस चर्चा ने गुगवारा के सबसे पिछड़े हुये आदिवासी माने जाने वाले सहरिया परिवारों को जीवन व्यवहार बदलने के लिये मजबूर कर दिया। मल-निपटान के लिये सभी 48 परिवारों ने बेहतर व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से गड्ढे खोदे। यहां प्रशासन ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि के कुछ दिन स्व-प्रेरणा और श्रमदान से यह व्यवस्था बनायें फिर समय स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत उन्हें पक्के शौचालय बनाने के लिये शासकीय अनुदान दिया जायेगा। चार माह गुजर गये और आदिवासियों द्वारा खोदे गये गड्ढे भी भर गये पर सरकार इस निर्मल ग्राम की तरफ रुख करना भूल गई। अब यह मान लेना जरूरी है कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। यदि यह विचार लागू नहीं हो पाया तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि वंचित परिवारों के स्वास्थ्य के बुनियादी अधिकार का हनन हुआ है।

उल्लेखनीय है कि अस्वच्छता और खुले में शौच व्यवस्था मध्यप्रदेश में हर वर्ष 11 हजार मौतों का कारण बनती है। 11 लाख प्रकरण मलेरिया और 30 लाख प्रकरण डायरिया जैसी बीमारी के सामने आते हैं। बीमारियों के कारण सामाजिक अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त बोझ पड़ता है। जब किसी गरीब परिवार के व्यक्ति पर इस तरह की बीमार का आक्रमण होता है तो न केवल उस पर इलाज का बोझ पड़ता है बल्कि रोज कमाकर रोज

पेट भरने की जद्दोजहद करने वाले ऐसे परिवारों को भूखे भी रह जाना पड़ता है। और बीमारी की पीड़ा से शुरु हुई प्रक्रिया गरीबी के मकड़जाल को और ज्यादा महीन बना देती है। गुगवारा में भी पिछले साल मलेरिया, डेंगू, डायरिया के कारण लगभग हर आदिवासी परिवार बीमार पड़ा था इसलिये स्वच्छता का उपाय उन्हें बेहद रास आया पर गरीबी के कारण वे इस उपाय को अपने संसाधनों से लागू नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें सरकारी सहायता की दरकार तो होती है परन्तु अब विश्वास टूटने जैसी स्थिति है। मसला केवल एक परिवार का नहीं है शिवपुरी में हुई गरीबी की रेखा जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि जिले के 238493 परिवारों में से 228839 परिवार तो खुले में ही शौच जाते हैं। जब कि दूसरी ओर गंभीर खाद्य असुरक्षा के बीच जीवनयापन करने वाले ये आदिवासी एक वर्ष में 1903 रुपये स्वास्थ्य की समस्याओं पर खर्च करने के लिए मजबूर होते हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था तो लगभग ध्वस्त हो चुकी है। वहां चिकित्सक ज्यादा से ज्यादा नब्ब देख, धड़कने गिन कर पर्चे पर दवाइयाँ तो लिख देता है पर जांच और दवाइयों के लिये तो दुकानदारों के पास ही जाना पड़ता है।

मध्यप्रदेश के संदर्भ में स्वास्थ्य और स्वच्छता के सवालों को विकास के लिये सबसे बड़ी चुनौती माना जाना चाहिये क्योंकि कमजोर और बीमार शरीर विकास की प्रक्रिया में बहुत उत्पादक भूमिका नहीं निभा सकता है। पर अफसोस कि सरकार के लिये स्वास्थ्य और स्वच्छता प्राथमिकता के मुद्दे नहीं हैं और इनके प्रति कोई राजनैतिक प्रतिबद्धता भी नजर नहीं आती है। समग्र स्वच्छता अभियान के खराब हश्र के लिये कोई मुहावरा या मिसाल भी अब नहीं मिल पा रही है। शिवपुरी जिले में पिछले वर्ष (वर्ष 2006-07 में) में यह लक्ष्य तय किया गया था कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 28653 परिवारों को व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय बनाने के लिये आर्थिक मदद दी जायेगी किन्तु वर्ष बीत गया और केवल 3405 (11.88 प्रतिशत) परिवार ही सरकारी प्रक्रिया से गुजर कर लाभ हासिल कर पाये। सामान्य परिवारों की स्थिति तो और भी बुरी है। केवल 4.01 प्रतिशत सामान्य परिवारों को ही अभियान में मदद मिल पाई।

वास्तव में निर्णय लेकर सोच को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया अब भी बहुत जटिल है। पंचायतों को गांव के जरूरतमंद परिवारों की सूची बनाने का ही अधिकार है। आर्थिक संदर्भों में अंतिम निर्णय तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जिला प्रशासन के नौकरशाह ही लेते हैं। आज की स्थिति में भी, जबकि जवाबदेय शासन व्यवस्था बनाने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं, बिना 20 प्रतिशत राशि का कमीशन चुकाये विकास की प्रक्रिया टस से मस नहीं होती है। और चूंकि पंचायत प्रतिनिधियों को कागजी अधिकार तो मिले हैं किन्तु सामाजिक-राजनैतिक ताकत अब भी उन्हें नहीं सौंपी गई है, तो ऐसे में वे अफसरशाहों के सामने सिर झुकाये खड़े गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं हैं। आज का समय सूचना के अधिकार

और पारदर्शिता का समय है। माना यह जाता था कि जब सूचनार्ये सरकारी नकाब से बाहर आर्येगी तो व्यवस्था का असली चेहरा सामने आयेगा और प्रशासन या क्रियान्वयन एर्येसिया चाक-चौबंद हॉगी, परन्तु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को यह बताने में कोई हिचक नहीं हो रही है कि हाल ही में समाप्त हुए 2006-07 के वित्तीय वर्ष में जहां 3311313 शौचालय (गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार) बनाने के लिये सहयोग देने का लक्ष्य तय किया गया था उसमें से केवल 20.21 फीसदी यानी 669320 व्यक्तिगत शौचालय बनाने का ही लक्ष्य पूरा किया जा सका। यह भी सरकारी आंकड़ा है यदि इनका कभी सामाजिक अंकेक्षण कराया जाये तो पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की दर के अनुरूप आधे शौचालय तो अफसरों और भ्रष्ट प्रतिनिधियों की जेब में पहुंचे हैं।

भारतीय शासन व्यवस्था में बच्चे तो आज भी कतार में सबसे पीछे खड़े हुये हैं। वर्ष 2005 में लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने यह दावा किया था कि 31 मार्च 2006 तक प्रदेश के हर स्कूल में स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था होगी। तब मध्यप्रदेश के 56583 स्कूलों में शौचालय ही नहीं थे। परन्तु 31 मार्च 2007 भी बीच चुका है और 20974 स्कूलों में अब तक शौचालय नहीं बन पाये हैं। इतना ही नहीं 9343 स्कूलों के शौचालय जर्जर और अस्वच्छ स्थिति में हैं। जब स्कूलों की कल्पना की जाती है तब यह माना जाता है कि वहां एक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिक का निर्माण होता है किन्तु मध्यप्रदेश के 21 हजार स्कूलों के 36 लाख बच्चों को तो शौचालय की सुविधा ही नसीब नहीं हो रही है।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम (एकीकृत बाल विकास सेवार्ये) छह वर्ष की उम्र तक के बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए चलायी जाने वाली एकमात्र योजना है और बच्चों को स्वच्छ रखना और स्वच्छता का व्यवहार सिखाना इसका बुनियादी उद्देश्य है किन्तु राज्य की 49787 आंगनबाड़ियों में से 37457 आंगनबाड़ियों (यानी 75.3 फीसदी) में भी बच्चों के लिये स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। बीते वर्ष में सरकार ने इनमें से 6923 आंगनबाड़ियों में स्वच्छ शौचालय बनाने का लक्ष्य किया था, पर बने कुल 2309। वास्तव में लक्ष्य तय करने के मामले में तो राज्य बहुत सम्पन्न है किन्तु लक्ष्य पूरे करने के मामले में सबसे गरीब। सरकार चूंकि अपने विकास की प्राथमिकतार्ये खुद तय नहीं कर रही है, अब उसका पूरा ध्यान बाजार के लिये सुविधार्ये विकसित करने पर इसीलिये जमीनी समस्याओं और सरकार के प्रयासों के बीच मेल नहीं बैठ पा रहा है। यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अफसर योजनार्ये तो बना रहे हैं किन्तु राजनैतिक प्रतिबद्धता का कहीं नामो-निशान नजर नहीं आता है और जहां तक स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका की बात है, तो अफसोस कि उन्होंने निगरानी करने और सरकार को जवाबदेय बनाने की बजाये स्वयं ही शौचालय बनाने वाले ठेकेदारों की भूमिका निभाना शुरु कर दिया।

भारतीय रेल का योगदान

सामान्य रूप से नीति बनाने और क्रियान्वित करने वाले यह मानते हैं कि अशिक्षित और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार या लोग ही खुले में शौचालय जाने की परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वे ही इस व्यवहार को स्थाई बनाये रखे हुये हैं। इसी सोच के आधार पर सरकार ने समग्र स्वच्छता अभियान की रूपरेखा बनाई और पिछले सात सालों से इसे बनाये रखने की जद्दोजहद कर रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों की सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि वे यह समझ सकें कि खुले में शौच करना असभ्यता और असुरक्षा का पैमाना है। अब तो ऐसे लोगों को गरीब भी माना जाने लगा है। ऐसी सोच धारण करने वाली सरकार स्वयं रेल्वे के माध्यम से देश का सबसे बड़ा शौच कार्यक्रम संचालित कर रही है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलों में उपयोग में लाये जा रहे शौचालयों के जरिये डेढ़ करोड़ लोग रोज सरकारी सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब के लिये आज भी सरकार की कोई तैयारी नहीं है।

समग्र स्वच्छता अभियान की उपलब्धियां²

क्र	जिला	व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय (गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हेतु)			व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय (गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार)			सामुदायिक स्वच्छता परिसर		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	भोपाल	20010	1695	8.47	68894	2334	6.27	0	1	0
2	रायसेन	86722	15476	17.85	139180	5600	8.13	27	10	37.04
3	सीहोर	8683	4645	53.5	139180	2334	1.68	4	1	25
4	राजगढ़	79403	21619	27.23	102014	4499	3.23	44	9	20.45
5	विदिशा	58128	6513	11.2	153792	23150	22.69	14	3	21.43
6	बैतूल	76985	17025	22.11	92634	6260	4.07	44	6	13.64
7	होशंगाबाद	69432	37092	53.42	26756	32557	35.15	31	28	90.32
8	हरदा	22431	9930	44.27	759688	23199	86.71	3	4	133.33
9	इन्दौर	24795	19140	77.19	7848	12952	12.03	0	0	0
10	खण्डवा	96169	3818	3.97	10690	3169	40.38	47	2	4.26
11	बुरहानपुर	41047	2026	4.94	138550	3000	28.06	18	0	0
12	धार	75281	14295	18.99	88838	3045	2.2	13	2	15.38
13	झाबुआ	109136	21294	19.51	138955	15	0.02	5	4	80
14	खरगौन	73270	8659	11.82	67002	3464	2.49	20	20	100
15	बडवानी	77495	2300	2.97	138862	1200	1.79	20	2	10
16	उज्जैन	65443	10292	15.73	95405	10137	7.3	40	18	45
17	रतलाम	49456	13296	26.88	119498	9588	10.05	12	9	75
18	मंदसौर	42079	16781	39.88	69451	2739	2.29	0	0	0
19	नीमच	20000	4300	21.5	85164	43	0.06	3	2	66.67
20	देवास	55495	12866	23.18	101343	26742	31.4	50	27	54
21	शाजापुर	61222	14364	23.46	1067953	25287	24.95	16	9	56.25
22	ग्वालियर	30166	10638	35.26	70906	23115	35.5	13	12	92.31

23	दतिया	11958	925	7.74	58865	5706	8.05	10	0	0
24	गुना	52986	5728	10.81	70647	641	1.09	0	0	0
25	अशोकनगर	40741	3616	8.88	141115	500	0.71		0	0
26	शिवपुरी	28653	3405	11.88	137932	5654	4.01	24	2	8.33
27	मुरैना	36076	10152	28.14	74634	9075	6.58	7	1	14.29
28	श्यापुर	28105	1632	5.81	112335	1837	2.46	10	8	80
29	भिण्ड	41987	2689	6.4	109117	2246	2	20	2	10
30	सागर	145037	45148	31.13	120958	39518	36.22	22	2	9.09
31	छतरपुर	72600	7140	9.83	78451	2504	2.07	30	25	83.33
32	पन्ना	72600	8817	12.14	115548	4968	6.33	15	8	53.33
33	टीकमगढ	63789	6917	10.84	64001	9124	7.9	0	0	0
34	दमोह	93750	23680	25.26	1219619	6401	10	20	15	75
35	रीवा	175985	39402	22.39	190821	30906	37.55	0	0	0
36	सतना	153526	5340	3.48	105946	184	0.1	16	4	25
37	शहडोल	62830	22349	35.57	68324	1130	1.07	16	9	56.25
38	अनूपपुर	41887	15484	36.97	38376	0	0	11	15	136.36
39	उमरिया	32893	6646	20.2	121922	20080	52.32	10	12	120
40	सीधी	163930	11690	7.13	73354	2807	2.3	24	7	29.17
41	जबलपुर	106290	36752	34.58	85836	0	0	44	32	72.73
42	कटनी	53000	10065	18.99	93911	254	0.3	15	11	73.33
43	नरसिंहपुर	67857	21308	31.4	97199	5528	5.89	31	34	109.68
44	बालाघाट	171243	24050	14.04	53200	0	0	40	5	12.5
45	मण्डला	100000	26762	26.76	45000	2224	4.18	0	0	0
46	दिन्डोरी	50206	8923	17.77	106711	0	0	12	2	16.67
47	सिवनी	84536	45975	54.39	133487	20492	19.2	0	0	0
48	छिन्दवाडा	116000	6661	5.74	1296384	28967	21.7	0	0	0
योग		3311313	669320	20.21	4343644	443267	10.2	801	363	45.32

² लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, 31 मार्च 2007 की स्थिति.

समग्र स्वच्छता अभियान की सच्चाई³

क्र	जिला	स्कूल स्वच्छता			आंगनवाडी केंद्र				
		शौचालय बनाने का लक्ष्य	शौचालय बने	प्रतिशत	कुल आंगनवाडी केंद्र	शौचालय वाले केंद्र	शौचालय बनाने का लक्ष्य	शौचालय बने	प्रतिशत
1	भोपाल	361	112	31.02	1266	48	0	0	0
2	रायसेन	985	1076	109.24	849	162	0	0	0
3	सीहोर	1141	544	47.68	690	221	0	572	0
4	राजगढ़	1263	741	58.67	903	269	0	0	0
5	विदिशा	1904	555	29.15	848	156	145	2	1.38
6	बैतूल	1388	662	47.69	1583	309	0	29	0
7	होशंगाबाद	954	863	90.46	729	133	0	70	0
8	हरदा	355	233	65.63	353	183	223	15	6.73
9	इन्दौर	457	452	98.91	892	246	0	0	0
10	खण्डवा	916	261	28.49	1156	55	0	3	0
11	बुरहानपुर	322	28	8.7	578	189	0	0	0
12	धार	2721	819	30.1	2402	650	351	0	0
13	झाबुआ	2000	1336	66.8	1977	1854	175	113	64.57

14	खरगौन	1000	751	75.1	1401	326	532	7	1.32
15	बडवानी	1039	425	40.9	1121	312	375	7	1.87
16	उज्जैन	1188	590	49.66	1580	307	0	2	0
17	रतलाम	1172	626	53.41	1141	391	350	8	2.29
18	मंदसौर	500	500	100	792	352	0	0	0
19	नीमच	397	285	71.79	526	111	58	19	32.76
20	देवास	1546	1377	89.07	900	403	104	25	24.04
21	शाजापुर	1021	555	54.36	951	201	97	24	24.74
22	ग्वालियर	990	637	64.34	908	63	0	0	0
23	दतिया	644	270	41.93	509	78	33	25	75.76
24	गुना	1350	824	61.04	747	125	39	60	153.9
25	अशोकनगर	1006	655	65.11	415	83	47	26	55.32
26	शिवपुरी	1197	810	67.67	997	51	207	99	47.83
27	मुरैना	1389	352	25.34	1351	166	152	11	7.24
28	श्योपुर	656	269	41.01	491	6	500	27	5.4
29	भिण्ड	1000	642	64.2	1215	228	160	0	0

30	सागर	1599	801	50.09	1371	41	6	43	716.7
31	छतरपुर	2184	2246	102.84	893	284	230	141	61.3
32	पन्ना	1472	370	25.14	569	10	0	50	0
33	टीकमगढ	823	636	77.28	832	367	0	30	0
34	छमोह	713	571	80.08	756	47	89	36	40.45
35	रीवा	500	882	176.4	1583	102	0	0	0
36	सतना	2223	325	14.62	1333	33	26	0	0
37	शहडोल	1555	1463	94.08	878	120	371	127	34.23
38	अनूपपुर	1036	282	27.22	770	205	248	60	24.19
39	उमरिया	1217	534	43.88	542	81	26	26	100
40	सीधी	2817	2105	74.72	1350	0	112	55	49.11
41	जबलपुर	1387	1159	83.56	1287	524	0	71	0
42	कटनी	1474	789	53.53	933	168	251	100	39.84
43	नरसिंहपुर	993	860	86.61	701	583	0	30	0
44	बालाघाट	1600	1898	118.63	1670	174	1424	74	5.2
45	मण्डला	500	1110	222	1282	815	300	215	71.67

46	डिन्डोरी	1135	286	25.2	1048	0	292	35	11.99
47	सिवनी	1493	1142	76.49	1420	77	0	72	0
48	छिन्दवाडा	1000	900	90.00	1774	318	0	0	0
समग्र स्थिति		56583	35609	62.93	50263	11627	6923	2309	33.35

³लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, 31 मार्च 2007 की स्थिति.

समग्र स्वच्छता अभियान में व्यय⁴

क	जिला	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत (रु लाख)				जारी राशि (रु. लाख)				व्यय (रु. लाख)			
			केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही	कुल
1	भोपाल	24.03.2003	179.36	58.67	32.23	270.3	117.21	37.92	12.4	167.5	40.07	12.95	4.34	57.36
2	रायसेन	07.09.2000	717.05	227.25	142.02	1086	430.22	136.6	37.79	604.6	253.59	105.19	52.29	411.1
3	सीहोर	07.09.2000	239.39	94.22	35.47	369.1	215.46	130.13	8.6	354.2	141.4	56.48	21.55	219.4
4	राजगढ़	02.05.2002	731.7	238.56	143.36	1114	439.02	143.09	48.72	630.8	263.96	95.09	52.54	411.6
5	विदिशा	11.09.2003	615.67	226.34	115.67	957.7	184.7	67.9	23.33	275.9	176.22	63.8	23.6	263.6
6	बैतूल	23.01.2002	730.56	239.75	141.66	1112	438.34	156.35	34.07	628.8	207.19	67.39	34.98	309.6
7	होशंगाबाद	07.09.2000	624.87	198.86	119.97	943.7	374.92	119.13	50.51	544.6	260.97	103.04	50.51	414.5
8	हरदा	11.09.2003	194.33	64.64	37.15	296.1	116.6	38.78	19.39	174.8	87.54	34.8	21.23	143.6
9	इन्दौर	24.03.2003	235.22	76.01	40.13	351.4	211.7	68.4	5.98	286.1	141.27	61.98	11.51	214.8
10	खण्डवा	02.05.2002	802.05	246.57	152.63	1201	337.56	103.56	10.68	451.8	154.72	34.51	9.54	198.8
11	बुरहानपुर	02.05.2003	323.17	98.63	63.14	484.9	0	0	0	0	0	0	0	0
12	धार	11.09.2003	817.74	308.2	154.18	1280	490.64	184.92	8.27	683.8	258.9	107.83	48.01	414.7
13	झाबुआ	11.09.2003	848.34	302.88	178.8	1330	509	181.72	48.32	739	235.11	71.17	43.22	349.5
14	खरगौन	11.09.2003	577.18	197.68	120.25	895.1	173.16	59.29	0	232.5	165.09	61.97	42.06	269.1
15	बडवानी	11.09.2003	598.8	204.9	127.52	931.2	179.64	61.47	50.53	291.6	156.48	37.8	50.53	244.8
16	उज्जैन	1.07.2003	564.44	195.2	117.2	877.2	338.66	117.12	38.53	494.3	146.46	56.07	27.82	230.4
17	रतलाम	11.09.2003	473.03	167.4	90.61	731	283.82	100.44	14.35	398.6	175.1	84.87	24.2	284.2
18	मंदसौर	22.03.2003	354.44	111.76	62.6	528.8	212.66	67.07	16.43	296.2	97.27	31.57	17.32	146.2
19	नीमच	11.09.2003	183.84	61.29	34.13	279.3	55.16	18.37	7.8	81.33	52.35	20.7	9.25	82.29

20	देवास	11.09.2003	595.18	212.05	115.81	923	357.11	127.22	51.82	536.2	273.9	101.39	51.82	427.1
21	शाजापुर	11.09.2003	505.41	173.04	102.23	780.7	303.24	103.81	42.29	449.3	198.68	72.01	42.29	313
22	ग्वालियर	07.09.2000	370.03	126.77	63.49	560.3	222	76.05	33.7	331.8	168.14	68.44	34.69	271.3
23	दतिया	11.09.2003	190.28	68.12	30.99	289.4	57.09	20.43	4.2	81.72	44.76	18.16	6.23	69.15
24	गुना	11.09.2003	474.28	172.92	93.43	740.6	494	180.86	3.18	678	225.09	82.56	44.09	351.7
25	अशोकनगर	11.09.2004	349.07	128.53	71.28	548.9	0	0	0	0	90.71	35.29	15.96	142
26	शिवपुरी	11.09.2003	392.62	141.37	67.99	602	235.56	84.81	32.67	353	158.88	69.19	30.62	258.7
27	मुरैना	11.09.2003	425.04	155.87	75.74	656.7	255.01	93.51	21.03	369.6	138.57	47.58	19.81	206
28	श्यापुर	11.09.2003	292.83	101.17	53.75	447.8	87.85	30.35	11.19	129.4	64.51	26.9	11.2	102.6
29	भिण्ड	11.09.2003	422.41	146.42	79.28	648.1	126.72	43.92	0	170.6	161.54	53.63	1.11	216.3
30	सागर	11.09.2003	961.33	330.32	219.91	1512	576.8	198.2	87.2	862.2	372.3	145.55	87.2	605
31	छतरपुर	11.09.2003	734.31	270.76	144.58	1150	220.29	81.22	3.84	305.4	204.08	81.54	25.7	311.3
32	पन्ना	11.09.2003	609.69	215.39	124.69	949.8	182.91	64.61	0	247.5	96.95	36.1	19.62	152.7
33	टीकमगढ	24.03.2003	472.54	157.76	96.2	726.5	141.76	47.33	11.17	200.3	115.48	43.63	18.01	177.1
34	दमोह	11.09.2003	606.26	199.42	137.89	943.6	363.76	119.64	34.12	517.5	233.77	83.69	47.48	364.9
35	रीवा	24.03.2003	927.73	296.93	229.98	1455	556.64	178.14	0	734.8	450.48	106.81	53.78	611.1
36	सतना	11.09.2003	1075.5	379.95	241.3	1697	322.66	113.98	0	436.6	66.75	35.25	3	105
37	शहडोल	11.09.2003	570.78	210.08	116.55	897.4	284.89	104.85	34.8	424.5	197.6	79.52	45.54	322.7
38	अनूपपुर	11.09.2004	378.87	139.45	77.36	595.7	0	0	0	0	103.84	36.32	25.76	165.9
39	उमरिया	11.09.2003	382.72	138.42	68.59	589.8	114.83	41.52	11.71	168.1	108.84	41.79	18.89	169.5
40	सीधी	11.09.2003	1216.3	437.45	269.01	1923	364.89	131.23	0	496.1	309.19	126.01	57.18	492.4
41	जबलपुर	11.09.2003	778.16	267.66	173.8	1220	494.86	169.7	95.14	759.7	383.76	133.51	95.14	612.4
42	कटनी	11.09.2003	535.43	192.65	101.49	829.6	321.26	115.59	8.17	445	211.99	49.03	0	261
43	नरसिंहपुर	07.09.2000	623.85	199.15	118.69	941.7	374.32	119.5	8	501.8	362.81	117.95	54.22	535

44	बालाघाट	11.09.2003	1138.9	394.93	265.17	1799	683.36	236.95	0	920.3	429.48	172.08	81.58	683.1
45	मण्डला	25.03.2003	591.72	191.43	136.5	919.7	177.52	57.4	43.34	278.3	167.42	58.09	43.34	268.9
46	डिन्डोरी	11.09.2003	470.84	165.54	90.52	726.9	141.25	49.65	0	190.9	34.27	9.59	2.73	46.58
47	सिवनी	1.07.2003	651.22	229.01	135.53	1016	505.96	175.98	75.97	757.9	344.5	141.25	75.97	561.7
48	छिन्दवाडा	27.03.2003	721.5	241.63	165	1128	216.45	72.48	32.94	321.9	153.91	66.19	26.29	246.4
समग्र स्थिति			27276	9403	5575	42255	13291	4631	1100	19022	8886	3246	1584	13716

⁴लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, 31 मार्च 2007 की स्थिति.

सातवें साल में समग्र स्वच्छता अभियान⁵
वर्ष 2000-07

क्र	जिला	कुल स्वीकृत लागत	कुल जारी राशि	कुल व्यय	प्रतिशत (कुल स्वीकृत लागत में से व्यय)
1	भोपाल	270.3	167.5	57.36	21.22
2	रायसेन	1086	604.6	411.1	37.85
3	सीहोर	369.1	354.2	219.4	59.44
4	राजगढ	1114	630.8	411.6	36.94
5	विदिशा	957.7	275.9	263.6	27.52
6	बैतूल	1112	628.8	309.6	27.84
7	होशंगाबाद	943.7	544.6	414.5	43.92
8	हरदा	296.1	174.8	143.6	48.49
9	इन्दौर	351.4	286.1	214.8	61.12
10	खण्डवा	1201	451.8	198.8	16.55
11	बुरहानपुर	484.9	0	0	0
12	धार	1280	683.8	414.7	32.39
13	झाबुआ	1330	739	349.5	32.39
14	खरगौन	895.1	232.5	269.1	30.06
15	बडवानी	931.2	291.6	244.8	26.28
16	उज्जैन	877.2	494.3	230.4	26.26
17	रतलाम	731.0	398.6	284.2	38.87
18	मंदसौर	528.8	296.2	146.2	27.64
19	नीमच	279.3	81.33	82.29	29.46
20	देवास	923.0	536.2	427.1	46.27
21	शाजापुर	780.7	449.3	313	40.09
22	ग्वालियर	560.3	331.8	271.3	48.42
23	दतिया	289.4	81.72	69.15	23.89
24	गुना	740.6	678	351.7	47.50
25	अशोकनगर	548.9	0	142	25.86

26	शिवपुरी	602.0	353	258.7	42.97
27	मुरैना	656.7	369.6	206	31.36
28	शुजुड	447.8	129.4	102.6	22.91
29	डुडुड	648.1	170.6	216.3	33.37
30	सललर	1512	862.2	605	40.01
31	ऑतरडुर	1150	305.4	311.3	27.06
32	डनुनल	949.8	247.5	152.7	16.07
33	डीकडडड	726.5	200.3	177.1	24.37
34	दडुडु	943.6	517.5	364.9	38.67
35	रीवल	1455	734.8	611.1	42.00
36	सतनल	1697	436.6	105	6.18
37	शहडुल	897.4	424.5	322.7	35.95
38	अनुडडुर	595.7	0	165.9	27.84
39	उडरलडल	589.8	168.1	169.5	28.73
40	सीधी	1923	496.1	492.4	25.60
41	ऑडलडुर	1220	759.7	612.4	50.19
42	कडनी	829.6	445	261	31.46
43	नरसलंहडुर	941.7	501.8	535	56.81
44	डलललघलड	1799	920.3	683.1	37.97
45	डणुडलल	919.7	278.3	268.9	29.23
46	डलनुडुडी	726.9	190.9	46.58	6.40
47	सलवनुी	1016	757.9	561.7	55.28
48	ऑलनुदवलडल	1128	321.9	246.4	21.84
सडडुगुर सुथलतल		42255	19022	13716	32.46

⁵ लुक सुवलसुथुडु डलनुतुरलकी वलडुडुग, डडुडुडुडु सरकलर, 31 डलरुडु 2007 की सुथलतल.

मध्यप्रदेश में स्वच्छ शौचालय वाले स्कूल⁶

क्र	जिला	बालिकाओं के लिये स्वच्छ शौचालय वाले स्कूल (प्रतिशत में)	साझा शौचालय वाले स्कूल (प्रतिशत में)
1	भोपाल	48.0	62.6
2	रायसेन	26.3	40.3
3	सीहोर	29.1	45.7
4	राजगढ़	18.7	37.2
5	विदिशा	13.2	23.8
6	बैतूल	25.5	34.7
7	होशंगाबाद	24.3	51.3
8	हरदा	18.2	39.1
9	इन्दौर	16.2	33.9
10	खण्डवा	19.4	28.1
11	बुरहानपुर	11.6	15.6
12	धार	9.9	23.1
13	झाबुआ	7.6	29.6
14	खरगौन	16.5	24.3
15	बडवानी	10.6	23.3
16	उज्जैन	21.2	38.5
17	रतलाम	24.2	35.1
18	मंदसौर	28.0	39.4
19	नीमच	19.9	33.0
20	देवास	23.0	62.2
21	शाजापुर	24.6	42.0
22	ग्वालियर	23.7	43.9
23	दतिया	12.3	24.3
24	गुना	13.1	38.4
25	अशोकनगर	6.9	14.5
26	शिवपुरी	12.8	31.8

27	मुरैना	15.2	24.0
28	श्यापुर	6.6	13.7
29	भिण्ड	6.1	11.6
30	सागर	10.9	32.2
31	छतरपुर	10.7	21.0
32	पन्ना	8.1	25.6
33	टीकमगढ	9.7	29.0
34	दमोह	11.9	35.2
35	रीवा	4.2	8.3
36	सतना	7.8	20.4
37	शहडोल	5.5	23.6
38	अनूपपुर	5.0	14.6
39	उमरिया	13.2	45.5
40	सीधी	6.9	26.9
41	जबलपुर	19.4	39.1
42	कटनी	22.4	28.5
43	नरसिंहपुर	31.3	50.0
44	बालाघाट	35.9	45.1
45	मण्डला	9.2	45.8
46	डिन्डोरी	2.2	7.4
47	सिवनी	9.3	32.4
48	छिन्दवाडा	9.9	22.8
समग्र स्थिति		19.51	30.47

⁶ District Report Card 2006. National University of Educational Planning and Administration, New Delhi Ministry of HRD, Government of India. This report is released in April 2007.